



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]
No. 111]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1984/फाल्गुन 24, 1905
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1984/PHALGUNA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का. आ. 162 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए. / 84 :—केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का. आ. 613 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./76 दिनांक 15 सितम्बर, 1976 द्वारा इण्डस्ट्रियल रिकलमंडेशन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता (जिसमें इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45, टंगरा रोड, कलकत्ता और 3, पगलाबांग रोड, कलकत्ता स्थित औद्योगिक उपक्रमों के सम्पूर्ण प्रबंध को 15 सितम्बर, 1976 से पांच साल की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 697 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./81 तारीख 14 सितंबर, 1981 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रमों का एक वर्ष की अनिश्चित अवधि के लिए प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 665 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./82 तारीख 14 सितम्बर, 1982 का. आ. 174 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 14 मार्च 1983 तथा का. आ. 660 (अ)/18चक/18कक/आई. डी. आर. ए.-83 दिनांक 14 सितम्बर, 1983 द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध 14 मार्च, 1984 तक की अनिश्चित अवधि के लिए करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और केंद्रीय सरकार ने, यह राय होने पर कि सर्व साधारण के हित में यह समीचीन था कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखें, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (2) के परन्तक के अधीन एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि ऐसा प्रबंध तारीख 30 जून, 1984 तक की और अवधि के लिए जारी रखा जाए । और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने, तारीख 12 मार्च, 1984 के आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दो औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध तारीख 30 जून, 1984 तक की और अवधि तक जारी रखने के लिए अनुज्ञात कर दिया था ।

अतः केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18-कक के साथ पठित धारा 18-चक की उप-धारा (2) के परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत को निर्देश

बेटी है, कि वह तारीख 30 जून, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध करना जारी रखे।

[फा. सं. 2(19)/75-सी. यू. एस.]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 162(E)|18FA|18AA|IDRA|84.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)|18FA|18AA|IDRA|76, dated the 15th September, 1976 the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the 'authorised person') to take over the management of the whole of the two industrial undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta, and at 3, Pagladanga Road, Calcutta, owned by Messrs Bengal Potteries Limited, Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976;

And, whereas, by the order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development No. S.O. 697(E)|18FA|18AA|IDRA|81, dated the 14th September, 1981 the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period of one year;

And, whereas, by the order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 665(E)|18FA|18AA|IDRA|82 dated 14-9-1982, S.O. 174(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated the 14-3-1983 and S.O. 660(E)|18FA|18AA|IDRA|83 dated 14th September, 1983, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto 14th March, 1984.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it was expedient in the interests of the general public that the authorised person should continue to manage the said Industrial Undertakings, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

And, whereas, the said High Court by its Order dated the 12th March, 1984 permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(19)/75-CUS]

का. आ. 163 (अ)/18चख/उ. वि. वि. अ./84 :—
केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 39 (अ)/18चख/उ. वि. वि. अ./77, तारीख 22 जनवरी, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) यह घोषणा की थी कि :—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) इस अनुकूलों सहित की उक्त अधिनियम की धारा 9-क, 5-क, 5 (ख) और धारा 33-ग का लोप किया जाएगा, सेर्स बंगाल पोटररीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्वाधीन दो औद्योगिक उपक्रमों जो कि 45, टंगरा रोड, कलकत्ता और 3, पगलाडंगा रोड, कलकत्ता में स्थित हैं, को लागू होगा, और

(ख) राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संघिदाओं संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचादों, स्थायी आवेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन (उनसे भिन्न जिनका संबंध बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से है) जिनके उक्त औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की स्वामी कम्पनी पक्षकार है, या जो व्यवस्थित, उन औद्योगिक उपक्रमों या कम्पनी को लागू होते हों, और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकार विशेषाधिकार बाध्यताएँ और दायित्व निर्वाचित रहेगा,

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर और 14 मार्च, 1984 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 30 जून, 1984 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी जानी चाहिए,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अवधि 30 जून, 1984 तक के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 2(19)/75-सी. यू. एस.]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 163(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 39(E)|18FB|IDRA|77, dated the 22nd January, 1977 (hereinafter referred to as the said order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clauses (a) & (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that :—

- (a) the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), shall apply to the two industrial undertakings at 45 Tangra Road, Calcutta and 3 Pagladanga Road, Calcutta owned by M/s. Bengal Potteries Limited, Calcutta with the adaptation that section 9A, Chapters, VA and VB and section 33C of the said Act shall be omitted, and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said

industrial undertakings are parties, or the company owing such industrial undertakings, is a party or which may be applicable to the industrial undertakings of the company, as the case may be and all or any of the rights, privileges obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time and inclusive of the 14th March, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of sub-Section (1), read with sub-section (2) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[F. No. 2(19)|75-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

